

Ministry of Coal

Demise of Any Coal India Employee Due to Covid 19 Will Be Treated as Accidental Death: Shri Pralhad Joshi

Dependents to Get All Benefits

Posted On: 30 JUL 2020 7:32PM by PIB Delhi

Death of Coal India employees due to Corona Pandemic will be treated as accidental death and the kins of employee will get the same financial benefits as they get in the case of accidental death during duty, said Union Minister of Coal and Mines Shri Pralhad Joshi. Interacting with media in Ranchi on his one day visit to Jharkhand, Shri Joshi said that Coal India's around 4 Lakh on roll and workers on contract will get benefited from this decision. The kins of employees deceased from Covid so far will also get protected.

"Putting their lives in danger Coal Indians have performed a tremendous job during Covid pandemic. They are relentlessly doing a good job. That's why I proudly call them Coal Warriors. I have announced this benefit just to recognize their invaluable service to the nation.", Shri Joshi said.

The Minister further said that commercial coal mining is going to fuel development in Jharkhand in coming years. Under the commercial auction of 09 coal mines in Jharkhand, the State is expected to earn more than Rs. 3,200 crores in 1-year as revenue and almost 50,000 additional employment will be generated for the people of the State. Additionally, Jharkhand's contribution to DMF will be around Rs 17 crores which can be used for development of regions around coalfield areas.

"Response of commercial mining auction is very good. Specially in Jharkhand we are getting 5 to 10 bidders for almost all of the mines put on auction. The state will get benefited from it and it will chart a new chapter of growth in the state.", Shri Joshi said.

During his Ranchi visit Shri Joshi met Chief Minister of Jharkhand Shri Hemant Soren and discussed various mining related issues with him. He reviewed the performance of coal companies Central Coalfields Limited (CCL), Bharat Coking Coal Limited (BCCL) & Eastern Coalfields Limited (ECL) and appreciated the hard work being put through by the Coal Warriors in the last few months in fulfilling the power demands of the nation during the ongoing pandemic.

Stressing upon the need of commencement of commercial coal mining he said India still meets a fifth of its annual coal requirement through imports. Once commercial mining picks up, imports by independent thermal power plants and captive power plants are likely to be substituted, saving in potential import bill of around Rs 30,000 crore per every year. It will help in providing direct and indirect employment to more than 3 lakh manpower.

Highlighting the importance of mining for Jharkhand, Shri Joshi said that mining is the lifeline of Jharkhand and plays crucial role in its development.

He said that Jharkhand is the only State in the country to have 3 coal companies simultaneously excavating coal out of its mineral-rich soil. Coal companies CCL, BCCL & ECL are expected to mine out

742 million tonne (MT) of coal in the next 4 years, paying revenue of almost Rs. 18,889 crores. The State earned almost Rs. 4000 crores every year during the last 4 years i.e. around Rs. 16,000 crores. The holding company of these coal companies, Coal India Limited (CIL), pays about 30% of its total royalty to Jharkhand alone while the share of production from Jharkhand is about 20%.

The minister stated that the Union Government wants Jharkhand to progress and contribute to the growth of the nation's economy. Coal companies operating in the State have been working for decades now, excavating coal out of the mineral-rich soil of Jharkhand and paying revenue in return to the State for its development. An annual revenue of Rs. 6,564 crores is expected to accrue to the Jharkhand Government from the coal mines allocated under CMSP Act. Additionally, CIL will invest more than Rs. 37,000 crores by 2023-24 in Jharkhand to build its infrastructure.

RJ/NG

(Release ID: 1642415) Visitor Counter : 639

Read this release in: Urdu , Marathi , Hindi , Manipuri , Punjabi , Tamil , Telugu

कोयला मंत्रालय

कोविड-19 के चलते कोल इंडिया के किसी भी कर्मचारी की मृत्यु को दुर्घटनावश मृत्यु माना जाएगा: श्री प्रह्लाद जोशी

कर्मचारी के आश्रितों को मिलेगा हर लाभ

प्रतिष्ठित तिथि: 30 JUL 2020 7:32PM by PIB Delhi

केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते कोल इंडिया के कर्मचारियों की मृत्यु को दुर्घटना में हुई मृत्यु माना जाएगा और कर्मचारी के परिजनों को ऐसे सभी वित्तीय लाभ मिलेंगे जो उन्हें इयूटी के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में मिलते हैं। झारखंड की एक दिवसीय यात्रा के दौरान रांची में मीडिया के साथ संवाद में श्री जोशी ने कहा कि इस फैसले से कोल इंडिया के 4 लाख स्थायी और संविदा कर्मचारियों को फायदा होगा। अभी तक कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को भी इससे सुरक्षा मिलेगी।

श्री जोशी ने कहा, “कोविड महामारी के दौरान कोल इंडिया के कर्मचारियों ने अपनी जान को खतरे में डालकर शानदार प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि मैं उन्हें कोयला योद्धा (कोल वारियर्स) कहता हूँ। मैंने राष्ट्र के प्रति उनकी अमूल्य सेवाओं को सम्मान देने के लिए ही इस लाभ का ऐलान किया है।”

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कोयले का व्यावसायिक खनन आने वाले वर्षों में झारखंड के विकास का ईंधन बनने जा रहा है। झारखंड में 09 कोयला खदानों की व्यावसायिक नीलामी के अंतर्गत राज्य को राजस्व के रूप में एक साल में 3,200 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई होने का अनुमान है और राज्य के लोगों के लिए 50,000 अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा, डीएमएफ में झारखंड का योगदान लगभग 17 करोड़ रुपये होगा, जिसे कोयला खनन वाले क्षेत्रों के आसपास के इलाकों के विकास में उपयोग किया जा सकता है।

श्री जोशी ने कहा, “व्यावसायिक खनन के लिए प्रतिक्रिया अच्छी रही है। विशेष रूप से झारखंड में हमें नीलामी में शामिल सभी खदानों के लिए लगभग 5 से 10 बोलीदाता मिल रहे हैं। राज्य को इसका फायदा मिलेगा और इससे राज्य के विकास का एक नया अध्याय खुलेगा।”

रांची की यात्रा के दौरान श्री जोशी ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनके साथ खनन से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कोयला कंपनियों सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के प्रदर्शन की समीक्षा की, साथ ही मौजूदा महामारी के दौरान राष्ट्र की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए पिछले कुछ महीनों में कोल वारियर्स द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना की।

व्यावसायिक कोयला खनन शुरू किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत अभी भी अपनी कोयला जरूरतों का पांचवां हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। एक बार व्यावसायिक खनन शुरू होने पर स्वतंत्र पब्लिक बिजली परियोजनाओं और कैप्टिव बिजली संयंत्रों द्वारा किए जाने वाले आयात की भरपाई होने का अनुमान है, जिससे संभावित आयात बिल में 30,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की कमी आएगी। इससे 3 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने में सहायता मिलेगी।

झारखंड में खनन के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि खनन झारखंड की जीवन रेखा है और राज्य के विकास में यह अहम भूमिका निभाता है।

उन्होंने कहा कि झारखंड देश का ऐसा अकेला राज्य है, जहां उसकी खनिज संपन्न मिट्टी से 3 कोयला कंपनियां कोयले का खनन कर रही हैं। कोयला कंपनियां सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल द्वारा अगले

चार साल में 742 मिलियन टन (एमटी) कोयला निकाले जाने का अनुमान है, जिससे लगभग 18,889 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होगा। राज्य को पिछले 4 साल के दौरान प्रति वर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपये यानी कुल लगभग 16,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। इन कोयला कंपनियों की होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अपनी कुल रॉयल्टी का 30 प्रतिशत अकेले झारखंड को भुगतान करती है, जबकि उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार झारखंड का विकास और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उसके योगदान में बढ़ोतरी देखना चाहती है। राज्य में परिचालित कोयला कंपनियां यहां दशकों से काम कर रही हैं, झारखंड की खनिज संपन्न धरती से कोयले का खनन कर रही हैं और राज्य के विकास के लिए उसे राजस्व का भुगतान कर रही हैं। सीएमपीएस अधिनियम के अंतर्गत आवंटित कोयला खदानों से झारखंड सरकार को सालाना 6,554 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है। इसके अलावा, सीआईएल अपना आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए 2023-24 तक झारखंड में 37,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करेगी।

एसजी/एएम/एमपी/एसएस

(रलीज आईडी: 1642524) आगतुक पटल : 66

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Manipuri , Punjabi , Tamil , Telugu